बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 127 ● नई दिल्ली ● शनिवार 28 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

अब जब कोर्ट ने...केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत पर अन्ना हजारे ने क्या कहा

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में बरी करने के अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश अपनी न्यायपालिका की मजबूती के कारण सुचारू रूप से काम कर रहा है। अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा देश अपने ज्यूडिशियल और सिक्योरिटी सिस्टम की ताकत पर चलता है। अलग-अलग पार्टियों, जातियों, धर्मों और समुदायों वाला इतना बड़ा देश होने के बावजूद, यह ज्यूडिशियरी की वजह से आसानी से काम करता है। इसके बिना, अफरा-तफरी और अशांति होगी। अब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है, तो इसे मानना ही होगा।

मोदी और शाह ने की बड़ी साजिश, कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक- केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने अपने हाथ में गदा लेकर समर्थकों का अभिवादन किया। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रची। इन्हें जब लगा कि ये हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते तो इन्होंने ये साजिश की। आज पीएम मोदी और अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

मुझे जेल जाने से फर्क पड़ता है

केजरीवाल ने कहा कि मैंने सिर्फ ईमानदारी का काम किया। मुझे जेल जाने से फर्क पड़ता है। मैं वो राजनेता नहीं हूं जिसकी मोटी चमड़ी है। मेरे जेल जाने से मेरे परिवार पर फर्क पड़ता है। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि आज दिल्ली की क्या हालत कर दी है। मैंने दिल्ली में पांच हजार स्कूल बनाए, आप पांच सौ स्कूल बना कर दिखा दो। आज दिल्ली की सड़के कितनी खराब है। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैंने जितना काम दिल्ली के लिए किया आप उतना कर दो आपको चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल को जेल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कोर्ट ने झूठ का किला ढहा दिया

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने झूठ का किला ढहा दिया। देशभर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले चार साल से ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराब घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया। सीबीआई, ईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। आज कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा भी चलाया जा सके। कोर्ट का कहना है कि इतना गलत, फर्जी केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। यह पूरा षड्यंत्र किसने और क्यों रचा? यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रचा, उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस पर भी बरसे केजरीवाल

कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने की टाइमिंग को गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए कांग्रेस ने जहां सवाल उठाए तो अरविंद

केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा, मैं आपसे पूछता हूं कि केजरीवाल जेल गया, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गया? संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, क्या सोनिया गांधी जेल गई? कांग्रेसी किस मुंह से बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती?

सीबीआई देगी फैसले को चुनौती

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रथम दृश्य कोई भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है। कोर्ट सीबीआई मामले में सुनवाई कर रही थी। उधर, सीबीआई सूत्र के मुताबिक, सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी।

साउथ लॉबी ने दी थी 100 करोड़ रुपये की रिश्वत

इससे पहले 12 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और सभी आरोपियों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई में सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि पहली चार्जशीट और पूरक आरोप पत्र में साजिश के पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों की ओर से आरोपों को निराधार बताया था। सीबीआई का आरोप है कि साउथ लॉबी ने दिल्ली की आबकारी मामला अपने पक्ष में कराने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

रिश्वत लेने या मांगने का कोई प्रमाण नहीं

अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियां निभा रहे थे और उन्हें किसी भी तरह की रिश्वत मांगने या लेने से जोड़ने वाला कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि केजरीवाल का नाम पहली चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट में नहीं था, बल्कि चौथी पूरक चार्जशीट में जोड़ा गया, जो पहले की चार्जशीट का दोहराव है। बहस के दौरान अप्रूवर बने राघव मगुंटा के बयान का भी जिक्र हुआ था। बचाव पक्ष ने कहा कि ऐसा कोई सीधा लिंक नहीं है जिससे साबित हो कि केजरीवाल ने किसी से पैसे लेने को कहा था।

आखिर क्या है शराब नीति मामला?

कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया।

जांच कैसी शुरू हुई?

सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी।

सीबीआई की जांच ईडी की जांच से कैसे अलग है?

ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित थी।

फैसले के बाद केजरीवाल ने कही यह बात

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, -पिछले कुछ वर्षों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। सत्य की जीत हुई। आप को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, यह पूरा फर्जी केस था, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप कट्टर ईमानदार है। अच्छा काम करके सत्ता में आइए और झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।

डेली-वीकली न्यजू पेपर एसोसिएशन रजि. के अनिल शर्मा फिर चुने गए अध्यक्ष

संवाददाता-दिल्ली। दिल्ली डेली-वीकली न्यजू पेपर एसोसिएशन रजि. की मिटिंग में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया है कि अनिल कुमार शर्मा को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही कार्यकारिणी की भी घोषणा की गयी जो कि इस प्रकार से है इस मीटिंग शामिल पत्रकार जो कि इस प्रकार हैं: अनिल कुमार शर्मा (अध्यक्ष), भूपेन्द्र सिंह लूथरा (उपाध्यक्ष), सुनील शर्मा (उपाध्यक्ष), संदीप सिंह गोदरा (सलाहकार), राहुल शर्मा (महासचिव), पवन कुमार शर्मा (सचिव) और सोनिया शर्मा (सचिव) नियुक्त किए गये हैं। बी.के अवस्थी नोएडा, राजीव मित्रा, गाजियाबाद से नवल शर्मा और आकाश शर्मा, मुरादनगर से अर्जुन कुमार, मोदी नगर से राकेश राजपूत, मेरठ से शिवकुमार और सुभाष वर्मा, सहारनपुर योगेश अग्रवाल, बरेली से सुरेश गंगवार, लखनऊ से देवेन्द्र सिंह यादव, हरीश श्रीवास्तव इत्यादि लोग इस मीटिंग में शामिल रहे। इनकी ईमानदारी और संघर्ष को देखते हुए जिस तरह से इन्होंने छोटे-मझोले समाचार पत्रों के लिए संघर्ष किया और उसका समाधान कराया। इसी को देखते हुए विशेष रूप से सभी पत्रकार और प्रकाशनों एवं संपाकदों ने एक आवाज में बोला फिर से अनिल शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाए।

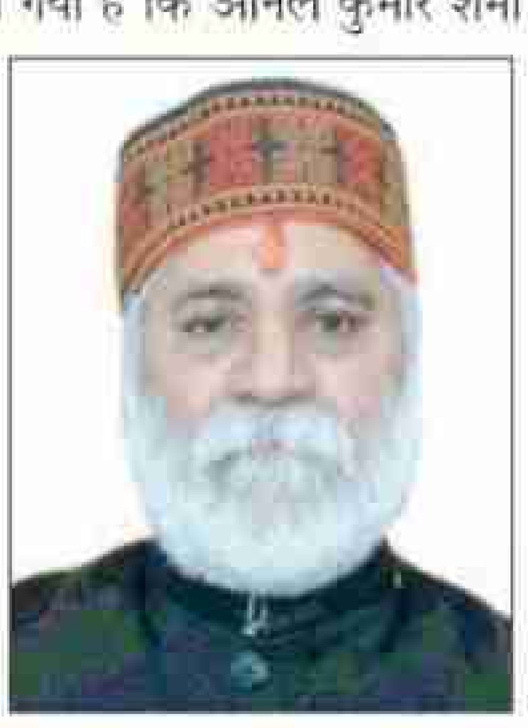

चांदनी चौक अतिक्रमण पर गहराया विवाद, 300 लोगों ने निकाला विरोध मार्च, बीजेपी ने एलजी को लिखा पत्र

नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अवैध अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस बीच टाउन हॉल से 300 लोगों ने विरोध मार्च निकाला है. वहीं चांदनी चौक नागरिक मंच और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर करीब 300 लोगों द्वारा टाउन हॉल से लाल किला तक निकाले गए विरोध मार्च पर कड़ी आपत्ति जताई है. बीजेपी प्रवक्ता और मंच के महासचिव प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जा करने के आरोप हैं, उन्हें जुलूस निकालने की अनुमति दी गई. जुलूस के दौरान जो जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है जैसे नारे लगाए गए. मंच ने यह भी आरोप लगाया कि इस जुलूस को स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस की सुरक्षा मिली. मंच का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों में सख्ती दिखानी चाहिए थी. पिछले कुछ समय से चांदनी चौक, जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच तनातनी बनी हुई है. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चांदनी चौक और जामा मस्जिद क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताई थी और नगर निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद कुछ जगहों पर हटाने की कार्रवाई भी हुई. व्यापारियों का कहना है कि सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे के कारण ट्रैफिक जाम, गंदगी और सुरक्षा की समस्या बढ़ रही है. वहीं, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोग अपने रोजगार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और वेंडर कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं. चांदनी चौक नागरिक मंच ने कहा है कि वह इस मुद्दे को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के सामने उठाया. मंच ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल, पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण का मुद्दा फिर से गरमा गया है और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है.

जेएनयू में बवाल के बीच फैकल्टी सदस्यों ने खोला मोर्चा, प्रोफेसर क्रिस्टु दास का आमरण अनशन शुरू

दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बृहस्पतिवार को हुए बवाल के बाद छात्र संघ और शिक्षक संघ के खिलाफ अब फैकल्टी सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूलों की तालाबंदी, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित करने, तोड़फोड़ और हंगामे के विरोध में जेएनयू ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर क्रिस्टु दास ने जेएनयू परिसर के साबरमती टी प्वाइंट पर आमरण अनशन बैठ गए है। प्रोफेसर के समर्थन में कई दूसरे फैकल्टी सदस्य और छात्र भी समर्थन के लिए मैदान में उतरे है जेएनयू प्रोफेसर क्रिस्टु दास ने कहा कि यहां तीन अलग-अलग भूमिकाओं में आमरण अनशन पर बैठा हूं। पहला जेएनयू में इतिहास के पूर्व छात्र के तौर पर, दूसरा राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में और तीसरा संकाय सदस्य के रूप में आमरण अनशन कर रहा हूं। परिसर में चल रही घटनाओं से सभी अवगत है। लाइब्रेरी में तोड़फोड़, उसके बाद छात्र संघ पदाधिकारियों के निष्कासन और फिर छात्र संघों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। विश्वविद्यालय में हड़ताल के नाम पर कक्षाओं में जबरन ताला लगाकर जेएनयू छात्र के पदाधिकारी जेएनयू शिक्षक संघ के समर्थन से तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे हैं। छात्रों को कक्षाओं से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। यह आमरण अनशन उन तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ है जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पर हंगामा, दरवाजे बंद और छात्रों और शिक्षकों को कक्षा में प्रवेश करने से रोका। हम बौद्धिक बहसों और चर्चाओं का स्वागत करते हैं। जेएनयू शिक्षक संघ और छात्र संघ को आकर बहस और खुली चर्चा करनी चाहिए। यह तोड़फोड़ के खिलाफ आमरण अनशन है। उन्होंने कहा कि अगर जेएनयू प्रशासन निष्कासन रद्द करने के लिए तैयार नहीं है तो छात्र संघ अदालत का रुख क्यों नहीं करता है उनको अदालत जाने से कौन रोक रहा है। जेएनयू कुलगुरु शांतिश्री डी पंडित की टिप्पणियों में छात्र संघ को कुछ कमियां नजर आती है तो जेएनयू हमेशा से बौद्धिक संस्कृति में विश्वास रखने वाला संस्थान रहा है। उन्हें सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित करना चाहिए था। जेएनयू के शोधार्थी छात्र ससार्थ शील ने कहा कि जेएनयू लंबे समय से लोकतंत्र का केंद्र रहा है। कुछ उपद्रवियों के एक समूह से खतरे में है। तोड़फोड़ के बाद भी वह रोजाना कक्षाओं में हंगामा कर रहे है। छात्रों को परेशान किया जा रहा है। कई इमारतों को बंद कर दिया है। जिस कारण कक्षाएं नहीं हो पा रही है। इस तरह के कृत्य के खिलाफ है। हम जेएनयू और इसके अध्ययन के माहौल को जेएनयू शिक्षक संघ और छात्र संघ की दुष्प्रचारियों से बचाने के लिए एकजुटता से खड़े हैं। हम जेएनयू में स्थिति सामान्य चाहते है।

होली से पहले नियम ताक पर, कानून जेब में रखकर जारी है निजी बसों की लूट; हर त्योहार का यही है रंग

नई दिल्ली । घर पहुंचने की मजबूरी में निकले यात्रियों की भीड़ को मौका मानकर दिल्ली के अंतरराज्यीय बस अड्डों पर निजी बस संचालकों की लूट खुलकर जारी है। ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं हैं और सरकारी बसें पहले से भरी चल रही हैं। ऐसे में मजबूर यात्रियों से तय किराए के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। आम दिनों के मुकाबले कई रूटों पर किराया दोगुना तक वसूला जा रहा हैघर जाने वाले यात्रियों का कहना है कि होली से पहले निजी बसों में नियम ताक पर हैं और कानून उनकी जेब में। नहीं चाहते हुए भी दोगुना किराया देना मजबूरी है वरना त्योहार परिजनों के साथ मना नहीं पाएंगे। बस अड्डे पर अपने परिवार के साथ खड़े यात्री अनिकेत ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले हैं और होली पर हर साल घर जाते हैं। इस बार ट्रेन में वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण उन्हें बस से जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि किराया बहुत यादा है, लेकिन त्योहार पर घर जाना जरूरी है, इसलिए मजबूरी में पैसा देना पड़ रहा है। अन्य यात्री आशुतोष ने बताया कि ऑनलाइन टिकट नहीं मिलने पर वह सीधे बस अड्डे पहुंचे। यहां आकर पता चला कि किराया दोगुना लिया जा रहा है। बस अड्डों पर जुटे यात्रियों और चालकों से मिली जानकारी के अनुसार, लंबे रूटों पर किराया दोगुना तक कर दिया गया है। निजी वेबसाइटों और ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी किरायों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ट्रैवल वेबसाइटों पर भी होली से पहले टिकट दरों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वेबसाइटों पर सामान्य दिनों की तुलना में 30 से 80 प्रतिशत तक किराया बढ़ा हुआ है। वहीं, कई रूटों पर सीटें सोल्ड आउट दिख रही हैं।

दिल्ली से वाराणसी, लखनऊ और कानपुर का किराया सामान्य दिनों में 700 से 1200 के बीच है जबकि निजी बस चालक 1500 से 2000 रुपये तक वसूल रहे हैं। जयपुर और हरिद्वार के लिए 1000 से 1300 रुपये तक किराया लिया जा रहा है। आम दिनों में यह किराया लगभग 500 से 800 रुपये होता है। दिल्ली से पटना के लिए 2000 से 3500 रुपये प्रति सीट तक वसूले जा रहे हैं जबकि मथुरा का किराया 1200 रुपये तक मांगा जा रहा है।

भीड़ के कारण बढ़ा रहे किराया

निजी बस चालक रानू ने बताया कि होली के कारण बसों में भीड़ है। उन्होंने बताया कि सीटों की मांग बहुत यादा है।

कई बार हमें अतिरिक्त स्टाफ और अतिरिक्त फेरे लगाने पड़ते हैं। डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, इसलिए किराया थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि आगे किराये में और बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ बस ऑपरेटरों ने यह भी बताया कि त्योहार के दौरान मांग और आपूर्ति के आधार पर किराया तय होता है।

भीड़ से बढ़ रही अव्यवस्था

आनंद विहार और सराय काले खां बस अड्डों पर लंबी कतारें, सामान के साथ खड़े परिवार और टिकट के लिए होड़ का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। कई यात्री घंटों से बस का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों के मुताबिक, सुरक्षा और सुविधा दोनों प्रभावित हो रही हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होली जैसे बड़े त्योहार पर घर जाने की खुशी किराये की मार के कारण फीकी पड़ती नजर आ रही है। लोग अतिरिक्त पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि समय पर अपने गांव और शहर पहुंच सकें। यात्रियों के अनुसार, सरकार और परिवहन विभाग को त्योहारों के दौरान विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। यात्री शिवी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब हर साल होली, दिवाली और छठ जैसे पर्व पर भीड़ बढ़ती है, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती। अभी तो होली में 6 दिन बाकी है, धीरे-धीरे हालात और खराब होने वाले है। त्योहार की खुशियां तभी पूरी होंगी जब सफर आसान और सुलभ होगा। फिलहाल, घर जाने की जल्दी में यात्री महंगे टिकट खरीदने को मजबूर हैं और बस अड्डों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है।

नशाखोरी

भारत में किशोरों के बीच नशीले पदार्थों के सेवन का मुद्दा उठते ही डर लगना स्वाभाविक है। साथियों के दबाव, शैक्षणिक तनाव और नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता जैसे कारकों के कारण भारतीय किशोरों में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 10-17 वर्ष की आयु के लगभग 1.3 प्रतिशत बच्चे शराब का सेवन करते हैं। प्रारंभिक जागरूकता और समय पर हस्तक्षेप से दीर्घकालिक नुकसान को काफी हद तक कम किया और स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सकता है। समस्या की पहचान और उसके शुरुआती चरण में ही उसका समाधान करने से नशीले पदार्थों पर निर्भरता की रोकथाम की संभावना काफी बढ़ जाती है। किशोरों में नशीले पदार्थों के सेवन के कुछ विशिष्ट व्यावहारिक संकेत होते हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले किशोर अपने साथियों के समूह में बदलाव कर सकते हैं, वे अपने पुराने दोस्तों से दूर हो जाते हैं और ऐसे नए परिचितों की ओर आकर्षित होते हैं, जो उनके जैसा ही व्यवहार करते हैं। शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट, जैसे कि कम अंक आना, अनुपस्थिति बढ़ना या स्कूल में रुचि की कमी, छात्रों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का प्रारंभिक संकेत हो सकता है, जो संज्ञानात्मक कार्य और प्रेरणा को प्रभावित करता है। नींद में बदलाव, जैसे अनिद्रा या अत्यधिक नींद आना, नशीले पदार्थों के प्रभाव का संकेत दे सकते है। किशोरों को नशीले पदार्थों के सेवन के लिए अचानक और अत्यधिक नकदी की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जेब खर्च का तुरंत गायब हो जाना, बार-बार अतिरिक्त धन की आवश्यकता वाली 'आपातकालीन' स्थितियां, या घर से नकदी और कीमती सामान का गायब होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आंखों में जलन, अचानक वजन कम होना या बढ़ना, भूख कम होना या बढ़ना, और खराब व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे दिखाई देने वाले बदलाव किशोरों में नशीले पदार्थों के सेवन का संकेत दे सकते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले किशोर अक्सर सिरदर्द, मतली या सुस्ती जैसी अस्पष्ट स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायतें नशीले पदार्थों के सेवन के शारीरिक प्रभावों को छिपा सकती हैं। किशोरों में नशीले पदार्थों का सेवन अलगाव का कारण बन सकता है क्योंकि वे नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में अधिक ही मग्न हो जाते हैं। पहले पसंद किए जाने वाले शौक या पाठ्येतर गतिविधियों में रुचि या भागीदारी में कमी यह संकेत दे सकती है कि नशीले पदार्थों का सेवन उन शौकों पर हावी हो रहा है, जिन्हें वे कभी बहुत पसंद करते थे। किशोरों में नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़े जोखिम कारकों को समझना नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। कभी-कभी जोखिम जीन में ही निहित होता है। यदि परिवार के किसी करीबी सदस्य को नशे की लत रही है, तो किशोर द्वारा इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने की संभावना अधिक हो सकती है। यह कोई निश्चितता नहीं है लेकिन इसका मतलब यह है कि उनका शरीर और मस्तिष्क नशीले पदार्थों पर दूसरों की तुलना में अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जब हम इस जोखिम से अवगत होते हैं, तो हम अधिक सतर्क और सक्रिय हो सकते हैं। इससे परिवारों को शुरुआती बातचीत शुरू करने, कड़ी निगरानी रखने और कोई भी समस्या शुरू होने से पहले ही सही सहायता प्रदान करने में मदद मिलती है। साथियों का दबाव और सामाजिक प्रभाव भी किशोरों को नशे की ओर धकेल सकता है। अक्सर, किसी समूह में घुलमिल जाने या स्वीकार किए जाने की चाहत उन्हें ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती है, जो वे अकेले कभी नहीं चुनते। इन वर्षों में दोस्तों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किशोरों को यह समझाने की आवश्यकता है कि सच्ची दोस्ती के लिए वफादारी के खतरनाक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। जब किशोर मुखर होना और सकारात्मक संबंध बनाना सीखते है, तो वे अत्यधिक दबाव में भी स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए सशक्त महसूस करते है। युवाओं द्वारा लिए जाने वाले विकल्पों में मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब कोई युवा चिंता, अवसाद या अत्यधिक तनाव से जूझ रहा होता है, तो वह थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए नशीले पदार्थों का सहारा ले सकता है। कई लोगों के लिए, इसकी शुरुआत पार्टी करने की इच्छा से नहीं, बल्कि भावनात्मक दर्द से निपटने या उसे कम करने के तरीके से होती है। हमें व्यवहार को ही नहीं, बल्कि मूल कारण को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके प्रदान करके और खुलकर बात करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाकर, हम उन्हें दवाओं के बिना राहत पाने में मदद कर सकते हैं। जब युवा अपनी भावनाओं के लिए मदद मांगने में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनके द्वारा नशा लेने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पारिवारिक इतिहास, सामाजिक दबाव और भावनात्मक संघर्षों को समझकर, हम अपने बच्चों के लिए वास्तव में प्रभावी रोकथाम रणनीतियां बना सकते हैं।

फैशन जगत में सांवली युवती की धूम

भारत में गोरा रंग एक गहरा सामाजिक मुद्दा है, जिसे अक्सर सुंदरता, सफलता और उच्च सामाजिक स्थिति से जोड़ा जाता है।
औपनिवेशिक विरासत और ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों के कारण भारतीय समाज में गोरी त्वचा को पसंद किया जाता है जबकि काले रंग को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है। यह पसंद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक रूढ़िवादी सोच का हिस्सा है। रंग सुंदरता का प्रतीक है। विवाहों में गोरी त्वचा को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है और इसके लिए कई उत्पाद और प्रथाएं मौजूद हैं। हर कोई गोरी दुल्हन चाहता है। इतना ही नहीं शादीशुदा जोड़े बच्चों का रंग भी गोरा ही चाहते हैं।
औपनिवेशिक शासन (ब्रिटिश काल) से भी पहले से मौजूद है, जो आर्यों और द्रविड़ों के समय से चली आ रही है, जहां गोरे रंग को कुलीन माना जाता था। विस्तृत शृंखला है लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों में गोरी त्वचा के लोग अधिक आम हैं। भारतीय मीडिया, फिल्मों और गानों में अक्सर गोरी त्वचा को दीवाना या आकर्षक बताया जाता है। जो इस सोच को और मजबूत करता है। हालांकि, अब युवा पीढ़ी में इस सोच को बदलने की कोशिश हो रही है। लोग रंग के बजाय व्यक्तित्व और गुणों को महत्व दे रहे हैं लेकिन 'गोरापन' का आकर्षण अभी भी बना हुआ है। मानसिकता के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है। कई लोग और विज्ञापन अब रंगभेद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और गोरी त्वचा को ही एकमात्र सुंदरता का पैमाना मानने से इन्कार कर रहे हैं। दुनियाभर में सांवले रंग के लोग भी शीर्ष ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चमड़ी के रंग का टैलेंट से कोई संबंध नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो आप दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आज समाज का कोई भी क्षेत्र हो चाहे उद्योगजगत हो, व्यापार हो, स्टार्टअप हो, शिक्षा का क्षेत्र हो सांवले रंग के लोग अपनी प्रतिभा का सिक्का जमा रहे हैं। यह खुशी की बात है कि फैशन की दुनिया में भी मानसिकता काफी हद तक बदल चुकी है। भविता मांडवा भारत की दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें ब्रिटिश वोग मैगजीन में जगह मिली है। भविता मांडवा की यह उपलब्धि इतिहास रचने की भांति है। इसकी वजह यह है कि भविता मांडवा दूसरी ऐसी भारतीय हैं, जिन्होंने भारतीय सौंदर्य यानी डस्की स्किन टोन के साथ यह अवसर प्राप्त किया है। ये वो लड़की है जिसने फैशन इंडस्ट्री में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फिर से डिफाइन करने का काम किया है। उससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने यह इतिहास बनाया था और प्रियंका चोपड़ा भी भारत के डस्की टोन की मल्लिका हैं। भविता मांडवा एक तेलुगु परिवार में जन्मी युवती हैं। 25 साल की 5 फुट 9 इंच लंबी इस मॉडल का बचपन हैदराबाद में गुजरा है। उन्होंने हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उन्होंने न्यूयार्क में आगे की पढ़ाई की है। उसी दौरान भविता की पहचान डिजाइनर मैथ्यू ब्लेजी से हुई और भविता को 2025 के स्प्रिंग/समर शो में विशेष मॉडल के रूप में रैंप वॉक करने का मौका मिला। इसके बाद भविता मंडावा मेटियर्स डीआर्ट 2026 शनेल फैशन शो को ओपन करने वाली मॉडल बनीं। भविता ने अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि शैनेल फैशन शो की ओपनिंग मेरे लिए बहुत ही खास थी। पश्चिम के देशों में मेरी इस उपलब्धि ने इस आइडिया को जन्म दिया कि क्या भारतीय महिलाओं को ट्रेडिशनल रूप में सुंदर माना जा सकता है भारत में रंगभेद हावी है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और सुंदरता का पहला मापदंड ही यही है कि लड़की को गोरी होना चाहिए। वैसी दुनिया में भविता मांडवा की एचीवमेंट बहुत ही मायने रखती है। वोग की पत्रिका पर भविता मांडवा से पहले भी कई डस्की स्किन वाली लड़कियों ने जगह बनाई है लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, जिनमें प्रियंका चोपड़ा भी एक हैं। उन्होंने कहा, सांवली लड़कियां खुद को देखा हुआ महसूस करती हैं, यह जोर देते हुए कि उनकी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। अपनी भारतीय पहचान और प्राकृतिक विशेषताओं को अपनाकर, वह एक ऐसे उद्योग में समावेशिता की दिशा में एक व्यापक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने अक्सर विविध आवाजों को हाशिए पर रखा है। जहां चोपड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की चकाचौंध को कवर पर पेश किया, वहीं मंडावा एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शैक्षणिक उपलब्धि, डिजाइन में नवाचार और रैंप पर प्रभुत्व का संगम है। अपनी बुद्धिमत्ता, कलात्मकता और रैंप पर दमदार उपस्थिति के अनूठे मेल के साथ वह अंतर्राष्ट्रीय फैशन जगत में एक अहम नाम बनने के लिए तैयार हैं। उद्योग जगत के जानकार उन्हें मैथ्यू ब्लेज़ी जैसे डिज़ाइनरों के लिए प्रेरणास्रोत मानते हैं और कई क्षेत्रों में एक साथ काम करने की उनकी क्षमता उन्हें अपने साथियों से अलग करती है। भू-राजनीतिक तनाव के कारण, ब्रांड्स अब केवल लागत कम करने के बजाय लचीली और अनुकूलन आपूर्ति शृंखलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि वैश्विक झटकों का सामना किया जा सके।
वैश्विक फैशन में अब केवल पश्चिमी मानकों का अनुकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारतीय जैसे घरेलू परिधान और औपचारिक उपदेश तंत्र को महत्व मिल रहा है। भविता मांडवा भारतीय मॉडल युवतियों के लिए आदर्श बन सकती हैं। भारत में भी गोरी त्वचा के प्रति यह जुनून धीरे-धीरे बदल रहा है लेकिन अभी भी यह समाज में एक मजबूत धारणा के रूप में मौजूद है।

सम्पादकीय...

भारत-इजराइल रिश्ते

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इजराइल और भारत के संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इजराइल के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय विदेश नीति की पुरानी परम्पराओं को तोड़ने वाले साबित हुए। एक तरफ भारत की इजराइल से नजदीकियां बढ़ीं तो दूसरी तरफ भारत के खाड़ी देशों से संबंधों में भी गर्मजोशी आई। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और इजराइल एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा किया था तो ये आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि इससे भारत के करोड़ों मुसलमान अलग-थलग पड़ सकते हैं लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा नीत एनडीए घरेलू राजनीतिक प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। भारत ने जहां फिलिस्तीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखा तो दूसरी तरफ इजराइल से भी अपने रिश्तों का विस्तार किया। आतंकवाद को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताओं ने दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग को बढ़ावा दिया। हाईटेक हथियारों की भारत की मांग और उन्हें बेचने की इजराइल की उदारता ने मजबूत रक्षा व्यापार संबंधों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइली संसद नेसेटको सम्बोधित करते हुएइजराइल पर 7 अक्तूबर 2023 को हमास के हमले की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की और कहा कि नागरिकों की हत्या को किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने गाजा में शांति स्थापना की पहल को दृढ़ समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति के पैरोकार हैं। क्षेत्र के सभी लोगों के लिएन्यायपूर्ण और स्थायी शांति बहुत जरूरी है। जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान शामिल है। इस तरह प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के स्टैंड को नहीं छोड़ा साथ ही आतंकवाद पर चोट भी की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मैडल से नवाजा भी गया। यह पदक प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत नेतृत्व के माध्यम से भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करता है। अब यह तथ्य पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है कि इजराइल ने 1962 में चीन से, 1965, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत की गुपचुप ढंग से सैन्य मदद की थी और कारगिल युद्ध में इजराइली मदद से ही हमने पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की थी तब इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम किट और मिसाइलें दी थी। उस के बाद से ही दोनों देशों के रक्षा संबंधों की शुरुआत हुई। लोकतान्त्रिक देश भारत की विदेश नीति 90 के दशक तक इजराइल के प्रति भेदभाव की रही और हमने फिलिस्तीन के मुक्ति संग्राम का खुलकर समर्थन किया मगर इसमें भी कोई दोष नहीं था क्योंकि स्व. यासर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन के लोग भी अपने जायज हकों के लिए लड़ रहे थे और वह स्वतन्त्र देश का दर्जा चाहते थे। भारत ने इस संघर्ष में कूटनीतिक स्तर पर उनका साथ दिया। फिलिस्तीन के अस्तित्व में आने के बाद विश्व परिस्थितियों में अन्तर आया है और इजराइल ने अरब देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी में कई बार शान्ति प्रयास किये हैं जिनमें 'कैम्प डेविड' समझौता सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बदलती दुनिया में इजराइल की स्थिति में परिवर्तन आना लाजिमी था और इस माहौल में भारत के राष्ट्रहितों में परिवर्तन आना भी लाजिमी था।

फिर भड़की आग

जब केंद्र सरकार ने मणिपुर में दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ एक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, तो उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि विरोध भड़क उठेगा और वह भी उसी समुदाय की ओर से जिसे शांत करने की कोशिश की गई थी कुकी-ज़ो। मई 2023 में मणिपुर हिंसा की चपेट में था। बहुसंख्यक समुदाय मैतेई और कुकी-ज़ो

> **आरोप है कि कुकी-ज़ो परिषद और विधायकों के बीच बैठकों में यह तय हुआ था कि जब तक राज्य या केंद्र उनकी मांगें नहीं मानते, वे सरकार से दूर रहेंगे। ऐसे में जो विधायक सरकार में शामिल हुए, उन्हें बहुमत की भावना के खिलाफ व्यक्तिगत निर्णय लेने वाला माना जा रहा है। इस भावना के साथ मैतेई नेतृत्व वाली सरकार के प्रति अविश्वास जुड़ जाए तो टकराव और गहरा जाता है। समुदाय के लोग याद दिलाते हैं कि एन. बीरेन सिंह के शासनकाल में कुकी-ज़ो लोगों की जानें गईं, वे घरों से बेदखल हुए और उनकी संपत्तियां नष्ट हुईं। ऐसे में उसी सत्ता तंत्र से उम्मीद रखना उन्हें निरर्थक लगता है। वे नई व्यवस्था को पुरानी बोतल में नई शराब करार देते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं बदला, क्योंकि जिनसे उनका संघर्ष है, मैतेई समुदाय, वे वही हैं। उनके अनुसार विवाद किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे समुदाय से है। यह भी स्वीकार करना होगा कि केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री के साथ एक नागा और एक कुकी नेता को उपमुख्यमंत्री बनाकर उसने सभी पक्षों तक पहुंचने और घाव भरने का प्रयास किया है। ऐसे में कुकी समुदाय द्वारा तीखी आपत्ति जताना न तो पूरी तरह उचित कहा जा सकता है और न ही न्यायसंगत।**

जनजातियों के बीच संघर्ष छिड़ गया था। यह टकराव उस न्यायालय आदेश के बाद हुआ जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। कुकी-ज़ो समुदाय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले से प्रभावशाली मैतेई और मजबूत होंगे, सरकार पर उनकी पकड़ बढ़ेगी और उनकी जमीनें भी छीनी जा सकती हैं। मुख्यत: मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की यह हिंसा धार्मिक नहीं, बल्कि जातीय आधार पर थी। यौन हिंसा, विस्थापन, हत्याएं और बदले की कार्रवाई आम हो गई। बेशक अल्पकालिक उपायों के तौर पर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, लेकिन इन्हें स्थायी शांति से पहले के अंतरिम कदम ही माना गया, यदि स्थायी शांति संभव हो भी सके। 2023 से मणिपुर अभूतपूर्व हिंसा का गवाह रहा है, जहां दोनों समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ संघर्षरत हैं। तीन वर्षों से अधिक समय से राज्य में विस्थापन, हत्याएं, दुष्कर्म और जातीय हिंसा का सिलसिला जारी है। इस वर्ष फरवरी में केंद्र ने नया शासन स्थापित करने की पहल की। 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इससे हिंसा थमी नहीं; उलटे हालात फिर भड़क उठे। नई सरकार के शपथ लेते ही कुछ घंटों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, सड़कें जाम कर दी गईं और बाजार व दफ्तर बंद कर दिए गए। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान ही उनके एक उपमुख्यमंत्री पर हमले की खबर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे सिंह विधानसभा अध्यक्ष और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वे बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से आते हैं, जिसका कुकी-ज़ो अल्पसंख्यकों से तीखा टकराव रहा है। अतीत में सरकार पर घटनाक्रम को अनदेखा करने और लोगों को मरने के लिए छोड़ देने जैसे आरोप लगते रहे हैं। इसी महीने जब सरकार ने सिंह को संकटग्रस्त राज्य की कमान सौंपी, तो इसे कई लोगों ने महज दिखावा बताया, आम धारणा यही रही कि दिखने में अच्छा, पर भीतर से खोखला। संतुलन साधने की कोशिश में सरकार ने सिंह के साथ दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए, एक नागा और एक कुकी-ज़ो समुदाय से। परिस्थितियों में इसे सकारात्मक कदम माना गया और उम्मीद जताई गई कि कम से कम शांति की झलक लौटेगी, लेकिन यह संभावना दूर होती दिख रही है। कुकी-ज़ो समुदाय के कुछ वर्गों ने अपने ही विधायकों के सरकार में शामिल होने की निंदा की है। उनका आरोप है कि अपने ही लोग दुश्मन यानी मैतेई पक्ष में चले गए, जिसे वे विश्वासघात मानते हैं। इसी व्यापक आक्रोश के बीच उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन निशाने पर हैं। राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री किपगेन को सुरक्षा कारणों से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ लेनी पड़ी। कुकी-ज़ो समुदाय अपने लंबे समय से लंबित अलग प्रशासन की मांग पूरी होने तक विरोध जारी रखने के संकेत दे चुका है। साथ ही, वे उन विधायकों के बहिष्कार पर भी अड़े हैं जिन्होंने सरकार का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इसी बीच उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने संवाद, उपचार और समावेशी शासन का आह्वान करते हुए खाई पाटने की अपील की, लेकिन यह गुहार कम से कम कुकी समुदाय के एक हिस्से तक तो बेअसर ही रही। कुकी-ज़ो समुदाय के प्रमुख नेता और मुख्य प्रवक्ता गिंज़ा वुआलज़ोंग ने कहा, जिन्होंने हमें धोखा दिया, उन पर हम कैसे भरोसा करें स्थिति को शांति से बहुत दूर बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कुकी और मैतेई समुदायों के बीच कोई समझौता नहीं होता, हालात सामान्य नहीं हो सकते। उनके अनुसार, सरकार हमें नई सरकार स्वीकार करने के लिए मजबूर करती दिख रही है, चाहे हमें पसंद हो या नहीं। वुआलज़ोंग और कई अन्य नेताओं ने माना कि शांति बंदूक की नोक पर नहीं, बल्कि बातचीत से संभव है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ वार्ता जारी है, पर मेज मैतेई नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ नहीं हो सकती। उनका तर्क है कि अतीत में ऐसे प्रयास विफल रहे हैं, इसलिए अब उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। कुकी-ज़ो समुदाय अपने विधायकों के सरकार में शामिल होने को जनता की इच्छा के विरुद्ध कदम बताते हुए खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आरोप है कि कुकी-ज़ो परिषद और विधायकों के बीच बैठकों में यह तय हुआ था कि जब तक राज्य या केंद्र उनकी मांगें नहीं मानते, वे सरकार से दूर रहेंगे। ऐसे में जो विधायक सरकार में शामिल हुए, उन्हें बहुमत की भावना के खिलाफ व्यक्तिगत निर्णय लेने वाला माना जा रहा है। इस भावना के साथ मैतेई नेतृत्व वाली सरकार के प्रति अविश्वास जुड़ जाए तो टकराव और गहरा जाता है। समुदाय के लोग याद दिलाते हैं कि एन. बीरेन सिंह के शासनकाल में कुकी-ज़ो लोगों की जानें गईं, वे घरों से बेदखल हुए और उनकी संपत्तियां नष्ट हुईं। ऐसे में उसी सत्ता तंत्र से उम्मीद रखना उन्हें निरर्थक लगता है। वे नई व्यवस्था को पुरानी बोतल में नई शराब करार देते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं बदला, क्योंकि जिनसे उनका संघर्ष है, मैतेई समुदाय, वे वही हैं। उनके अनुसार विवाद किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे समुदाय से है। यह भी स्वीकार करना होगा कि केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री के साथ एक नागा और एक कुकी नेता को उपमुख्यमंत्री बनाकर उसने सभी पक्षों तक पहुंचने और घाव भरने का प्रयास किया है। ऐसे में कुकी समुदाय द्वारा तीखी आपत्ति जताना न तो पूरी तरह उचित कहा जा सकता है और न ही न्यायसंगत। दरअसल यह केवल शुरुआत है और प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए इस समय धैर्य और संयम की आवश्यकता है, न कि मेरी मर्जी या कुछ नहीं जैसा रुख, जो फिलहाल कुछ वर्ग अपनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रवैया न केवल मणिपुर राज्य के हितों और संभावित शांति पहलों को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उन रचनात्मक प्रयासों को भी पटरी से उतार सकता है जो हालात को शांत करने और जख्मों पर मरहम लगाने के लिए किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यह आशंका भी नकारा नहीं जा सकती कि अशांति को भड़काने और विस्तोपित करने में बाहरी तत्वों की भूमिका हो।

विरोध के मंच और तरीके से कांग्रेस की साख पर सवाल

उमेश चतुर्वेदी।

विरोध और मतभिन्नता लोकतंत्र का आभूषण होता है। लेकिन विरोध का तरीका क्या हो या फिर किस जगह पर हो, इसकी समझ होनी चाहिए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। स्वाधीनता आंदोलन के साथ-साथ इतिहास के हर आगे बढ़ते पग के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती रही है। विरोधी आंदोलन चलाने का स्वाधीनता के पहले उसका लंबा इतिहास रहा। आजादी के बाद सबसे ज्यादा वक्त शासन का अनुभव भी उसी के पास है। इस वजह से उससे लोकतांत्रिक विरोध के तरीकों और विरोध के लिए चुने जाने वाले मंचों को लेकर विशेष उम्मीद रखना बेमानी नहीं है। शायद यही वजह है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में उसकी ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। पूर्व पत्रकार पवन खेड़ा जैसा प्रवक्ता 20 फरवरी के विरोध प्रदर्शन को चाहे जितना भी वाजिब ठहरा रहा हो, कांग्रेस की इस विरोध प्रदर्शन के लिए किरकिरी ही हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक ज्यादातर मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का साथ देने वाले ज्यादातर विपक्षी दलों को भी युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नहीं रूचा है। ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस प्रदर्शन को अनुचित बताया है। अखिलेश यादव ने शायद सबसे गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर ऐसा विरोध प्रदर्शन उचित नहीं था। अखिलेश यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से नसीहत देते हुए कहा कि देश को विदेशी प्रतिनिधियों के सामने शर्मिंदा करने से बचना चाहिए। कांग्रेस के साथ हर मुमकिन मौके पर गलबहियां डालकर चलने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने भी एक तरह से कांग्रेस को उपदेश ही दिया है। मनोज झा का कहना है कि शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन विरोध का तरीका बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं कि भारतीय लोकतंत्र में विरोध की परंपरा नहीं रही है। भारतीय राजनीति के चिर विद्रोही कहे जाने वाले लोहिया ने विरोध करने का जो मुहावरा दिया, वह भारतीय राजनीति का सर्वस्वीकार्य रहा है। उन्होंने संसद से सड़क तक विरोध का तरीका बताया। लोहियावादी विरोध कई मायनों में आक्रामक ही कहा जाएगा। लेकिन विरोध कब और कहां किया जाना चाहिए, उसकी जगह क्या होनी चाहिए, इसे लेकर भी भारतीय राजनीति में आमराय रही है। विरोध के मंच ऐसे नहीं होने चाहिए, जिससे भारत को एक राष्ट्र के रूप में वैश्विक शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सूत्र वाक्य को भारतीय राजनीति अपनाती रही है। लेकिन नई दिल्ली के भारत मंडपम में बीस फरवरी को युवा कांग्रेस की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन इस सूत्र वाक्य का एक तरह से उल्लंघन ही माना जाएगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के समर्थक और साथी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं या फिर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। जिस इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के मंच का इस्तेमाल युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए किया, उसमें दुनिया भर के 118 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 16 फरवरी से 21 फरवरी तक चले इस सम्मेलन में 22 देशों के शासनाध्यक्षों और मंत्री स्तर के 59 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के बाद जो नई दिल्ली घोषणापत्र जारी किया गया, उस पर 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताई है। जिसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे प्रमुख देशों की भी भागीदारी है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक वैश्विक स्तर के एआई नेता और 500 से अधिक स्टार्टअप्स ने भी शिरकत की। इस सम्मेलन की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस के घोषणा पत्र में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले पैरिस में हुए एआई वैश्विक सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में अमेरिका और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर नहीं किया था। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक मामलों में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन एक ही खेमे के देश हैं। जाहिर है कि ऐसे मंच का महज प्रधानमंत्री के विरोध के लिए इस्तेमाल करना सही कदम नहीं माना जाएगा। भले ही इस विरोध प्रदर्शन को मायावती भी अनुचित बता चुकी हों, वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी गलत बता चुके हों, फिर भी कांग्रेस द्वारा इसे वाजिब ठहराया जाना साबित करता है कि पार्टी के केंद्रीय ढांचे में उचित-अनुचित का भेद करने वाली शख्सियतों की कमी हो गई है।

कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी खेमे में ही उसकी सत्ता से दूरी से उपजी हताशा को माना जा रहा है। लेकिन विपक्षी खेमा इसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराता है। कांग्रेस के कुछ अंदरूनी नेता भी मानते हैं कि राहुल गांधी की अगुआई वाली कांग्रेस के केंद्रीय घेरे में दूरगामी सोच वाले नेताओं की बहुत कमी हो गई है। इसलिए पार्टी में एकाधिकारवादी और बेपरवाह सोच हावी होती गई है। विपक्षी खेमे के साथ ही पार्टी के कुछ लोग मानते हैं कि अगर पिछले आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार को राहुल की अगुआई वाली कांग्रेस ने अपना नेता मान लिया होता या फिर इंडिया गठबंधन का संयोजक स्वीकार कर लिया होता तो संभवतः देश का इतिहास कुछ और होता। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के बरक्स नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं, जिनकी राष्ट्रव्यापी एक छवि है। नीतीश के पास बिहार के अतिरिक्त देश के दूसरे इलाके में जमीनी नेतृत्व और संगठन नहीं है। लेकिन उनकी पहचान पूरे देश में है और उनकी छवि भी विपक्षी खेमे के दूसरे नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा पाक-साफ है। मौजूदा कांग्रेस की कमी यह है कि वह अगले पल उठाए जाने वाले अपने हर कदम के परिणामों का आकलन राहुल गांधी की राजनिक सेहत के लिहाज से करती है। कांग्रेस आलानेतृत्व की सलाहकार मंडली नहीं चाहती कि विपक्ष में ऐसी कोई शख्सियत उभरे, जिससे राहुल की प्रासंगिकता कमजोर हो। मोदी के बरक्स लड़ाई में वह दूसरे किसी विपक्षी नेता को उभरते हुए नहीं देख सकती।

मोदी विरोध में कदम उठाते वक्त वह भूल जाती है कि उन कदमों का राजनीतिक हासिल क्या होगा फिर राहुल समर्थक मंडली उन्हें मोदी के बरक्स सिर्फ नैरेटिव केंद्रित राजनीति की ही सलाह देती है। इन वजहों से राहुल का विरोध भी देश को उनकी तरफ आकर्षित करने का माध्यम नहीं बन पा रहा है। भारत मंडपम् में पूरे पांच दिन चले कार्यक्रम के चलते समूची दिल्ली ट्रैफिक जाम से हलकान रही। इसका असर गुड़गांव और नोएडा के ट्रैफिक पर भी पड़ा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कल्पनाहीनता से ट्रैफिक में फंसकर दिल्ली तकरीबन पूरे पांचों दिन हांफती रही। इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का ध्येय वाक्य 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' को भी लोग कोसते दिखे। कहने का मतलब यह है कि इस सम्मेलन की अहमियत के बावजूद इससे एक बड़ा तबका हलकान रहा। अव्वल तो ऐसे माहौल में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होना एकदम नहीं दिखा। कांग्रेस हालांकि दावा करती है कि देश अब मौजूदा सरकार से नाराज है। अगर उसके ही दावों को सच मान लें तो होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देश हाथोंहाथ ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस आलानेतृत्व के कदम आम लोगों में भरोसा पैदा नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय सलाहकार मंडली की सलाहें जनता के दिलों में मोदी विरोधी हिलोरें पैदा नहीं कर पा रही हैं, तो इसकी वजह यही है कि पार्टी के विरोध करने के शऊर, मुद्दे और मंच सही नहीं हैं। इसी वजह से उनकी साख नहीं बन पा रही है। सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को पता है कि राजनीति में साख का क्या महत्व होता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचलेबसा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/39862)

2 मार्च को पूर्णिमा की मध्य रात्रि को होगा होलिका दहन

मुरादाबाद। राष्ट्रीय पुजारी परिषद की टोली की बैठक संरक्षक आचार्य डॉ. जगदीश प्रसाद कोठारी के निवास राम गंगा बिहार स्थित आवास पर हुई। जिसमें शास्त्र अनुसार निर्णय लिया गया कि 2 मार्च पूर्णिमा की भद्रापुझल मध्य रात्रि 1.30 से 4.00 बजे तक होलिका दहन किया जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। शाम को 7.00 के बाद खुलेंगे इसलिए रंग धुलैंडी 4 मार्च को होगा। बैठक में राष्ट्रीय पुजारी परिषद के संरक्षक आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तौगी, महानगर की उपाध्यक्ष आचार्य पंडित विनीत शर्मा, पंडित नवल स्वरूप अवस्थी पुजारी माता मंदिर लाइन पार ,महामंत्री पंडित सतीश खंडूरी पुजारी शक्ति लोक शिवालय ,ज्योतिष आचार्य विजय कुमार दिव्य उपस्थित रहे ।

उपहार पाकर खिले बच्चों के चेहरें

इनरव्हील क्लब ने प्रेरणा स्कूल के बच्चों संग मनाई होली

मुरादाबाद। इनरव्हील क्लब मुरादाबाद ईस्ट द्वारा सामाजिक सरोकारों की कड़ी में आज झांझनपुर स्थित प्रेरणा स्कूल में होली मिलन समारोह का अत्यंत भावपूर्ण आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब की सदस्याओं ने स्कूली ब'चों के साथ न केवल गुलाल लगाकर होली मनाई, बल्कि उन्हें उपहार भेंट कर त्यौहार की खुशियां साझा कीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब प्रेसिडेंट वीना रस्तोगी ने की, जिनके द्वारा ब'चों को होली के लिए गुलाल, बलून, मास्क के साथ-साथ ताजे अंगूर और संतरे वितरित किए गए। बच्चों के उत्साह को दोगुना करने के लिए पीडीसी अनिता गुप्ता द्वारा 11 हजार रुपये की गुझिया व अन्य मिष्ठान भेंट किए गए। समारोह को और भी खास बनाने के लिए सपना अग्रवाल की ओर से बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया गया, जिसे पाकर ब'चे बेहद आनंदित दिखे। वहीं, प्राची दीक्षित द्वारा ब'चों को रंग-बिरंगी होली कैप, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट बांटे गए। गीता अग्रवाल के विशेष सहयोग से पूरे सेलिब्रेशन का संचालन और आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान क्लब प्रेसिडेंट वीना रस्तोगी ने कहा कि ब'चों के साथ त्योहार मनाना हमें आत्मिक शांति देता है। हमारा उद्देश्य इन ब'चों के जीवन में रंगों की फुहार लाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस अवसर पर क्लब की वरिष्ठ सदस्याएं और मार्गदर्शक मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जिनमें क्लब प्रेसिडेंट वीना रस्तोगी, पीडीसी ममता गर्ग, शालिनी भारद्वाज, सपना अग्रवाल, सरिता लाल, अनीता अग्रवाल, गीता अग्रवाल, दीपमाला त्यागी, आदि उपस्थित रहीं। सभी ने बच्चों को सुरक्षित और भाईचारे वाली होली मनाने का संदेश दिया।

धूमधाम से निकला रंग एकादशी का जुलूस

मुरादाबाद। महानगर में रंग एकादशी का जुलूस परम्परागत ढंग से निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों एवं शोकाकुल परिवारों के सदस्यों ने भाग लिया। झांकियां भी आकर्षण का केन्द्र रहीं। राष्ट्रीय पर्व होली समिति के तत्वावधान में रंग एकादशी का जुलूस खत्री धर्मशाला से प्रारम्भ हुआ, जो महानगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस चौकी के समीप सम्पन्न हुआ। रंग एकादशी के जुलूस में श्रीराम नवमी कमेटी के चेयरमैन राजेश रस्तोगी, महामंत्री पीयूष गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, शहर विधायक रितेश कुमार गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर, अरविन्द अग्रवाल जौनी, राजेन्द्र अग्रवाल, जुगनू जादूगर, धर्मेन्द्र यादव, मनोज व्यास, मुख्य आयोजन डा. एके टंडन, वैभव गोयल, श्याम खत्रा (सम्पादक), डॉ. मनोज रस्तोगी, अरुण गोयल, डॉ. प्रशान्त गुरु, मनोज गुप्ता एडवोकेट, महेन्द्र सिंह बब्बू, अतुल गुप्ता, विपिन गुप्ता, अंशुल गर्ग, देवेश वशिष्ठ, शिव कुमार सिंह, अरविन्द अग्रवाल जौनी, बाबा संजीव आकांक्षी, मनीष ुरी,सुभाष चन्द्र गुप्ता, चन्द्र शेखर शर्मा, सुरेश शुक्ला, आचार्य धीरशान्त दास, निमित जायसवाल, विचित्र कुमार शर्मा, कमल कुमार शर्मा, अतुल कुमार जौहरी, काव्य सौरभ जैमिनी, अजय अग्रवाल, श्याम बिहारी शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। दूसरी ओर आज अधिवक्ताओं ने जजी परिसर में होली खेली। गुलाल लगाकर एक-दूसरे को शुभकामनायें प्रदान की। न्यायिक स्टाफ ने भी पूरा सहयोग किया। होली पर्व मनाने में अध्यक्ष आनन्द मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता, अजय बंसल, आवरण अग्रवाल, दिलीप झा, प्रदीप सिन्हा बबली, राजेश वशिष्ठ, दीपक बजाज, प्रभात गोयल, महेश चन्द्र त्यागी, अजय उर्फ अतुल खोती, विनोद विग, आदीश कुमार जैन, मोहित शर्मा आदि मुख्य रहे।

शरई मालदार मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ अदा करने में न करे देरी- अहसन मियां

बरेली।

दूसरे जुमे पर मस्जिदों में अदा की गयी नमाज़।

पाक माह रमज़ान का आज दूसरा दूसरा जुमा और नौवां रोज़ा था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पुराना शहर,किला,जखीरा,जसोली,बाकर गंज,हुसैन बाग, आज़म नगर आदि में सुबह से ही रोज़ेदार नमाज़ की तैयारियो में लगे रहे। जुमा की मुख्य नमाज़ किला की शाही जामा मस्जिद में दोपहर डेढ़ बजे (1.30 बजे) अदा की गई। यहाँ भारी संख्या में नमाज़ियों ने शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम की इमामत में नमाज़-ए-जुमा अदा किया। इसके अलावा शहर की सभी प्रमुख दरगाहों,खानकाहों व मस्जिदों में दोपहर साढ़े बारह बजे से नमाज़ अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ। दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि दरगाह प्रमुख हज़रत सुब्हानी मियां व सज्जादानशीन मुफ़्ती अहसन मियां समेत सभी खानदान के बुजुर्गों ने सबसे आखिर में दोपहर तीन बजे रज़ा मस्जिद में नमाज़ अदा की। मुफ्ती ज़ईम रज़ा ने पहले खुत्बा पढ़ा इसके बाद नमाज़ अदा कराई। सभी के लिए खुसूसी दुआ की। यहाँ भी बड़ी संख्या में नमाज़ियों ने नमाज़ अदा कर दरगाह पर हाज़िरी दी। नमाज़-ए-जुमा अदा करने के बाद दरगाह के सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां ने कहा कि इस्लाम के पांच स्तंभ में एक ज़कात भी शामिल है। शरई मालदार मुसलमानों पर अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ की है। उन्होंने मुसलमानों से जल्द से जल्द ज़कात व सदका ए फित्र की रकम अदा करने को कहा। ताकि ज़कात के मुस्तहिक लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों व परेशान हाल लोगों की मदद करने का नाम और बंदों को अल्लाह से सीधे जुड़ाव का महीना रमज़ान है। इसलिए इस माह में जो जरूरतमंद रिश्तेदार,पड़ोसी जो किसी से मांगते भी नहीं लेकिन बेहद मजबूर और जरूरतमंद होते है उनका खास ख्याल रखे। इसके अलावा शहर की सभी मस्जिदों के इमामों ने खुत्बे से पहले रोज़ा,नमाज़ व कुरान व ज़कात पर रौशनी डाली। दरगाह ताजुशशरिया, खानक़ाह -ए-नियाज़िया, दरगाह शाह शराफ़त अली मियां, दरगाह शाहदाना वली, दरगाह वली मियां,दरगाह बशीर मियां, दरगाह वामिक मियां, सिविल लाइन्स की नौमहला मस्जिद, जसोली की पीराशाह मस्जिद, कचहरी वाली मस्जिद, आजम नगर की हरी मस्जिद, पुराना शहर की मिर्जाई मसजिद, नूरानी मस्जिद, हबीबिया, मस्जिद बीबी जी आदि में भी बड़ी तादात में नमाज़ियों ने जुमा की नमाज़ अदा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की।

डायट में दो दिवसी कार्यशाला का हुआ शुभारंभ

फतेहपुर।

नई शैक्षणिक रणनीति पर होगा मंथन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में दो दिवसीय कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। 27 से 28 फरवरी तक आयोजित इस कार्यशाला का संचालन प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक आरती गुप्ता के मार्गदर्शन में हो रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों को समझना, उनका विश्लेषण करना तथा जनपद स्तर पर प्रभावी शैक्षणिक कार्ययोजना तैयार करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ किया गया। सेवारत प्रशिक्षण प्रभारी विनय कुमार मिश्र तथा प्रवक्ता श्रीमती वीणा सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय संदर्भ समूह के सदस्य राधेश्याम दीक्षित एवं शैक्षिक संसाधन व्यक्ति संजय सिंह संदर्भदाता के रूप में उपस्थित रहे।

प्रारंभिक सत्र में विनय कुमार मिश्र ने कार्यशाला के उद्देश्यों एवं प्रतिभागियों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में परख व्यवस्था की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यचर्या, दक्षताएं तथा अधिगम परिणाम किस प्रकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 की परख योजना इन्हीं आयामों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति का आकलन संभव हो सके। आगामी सत्रों में जनपद फतेहपुर की परख रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रतिभागियों को परख संकेत पट पर उपलब्ध आंकड़ों को देखने एवं समझने की प्रक्रिया बताई गई। रिपोर्ट के आधार पर जनपद की शैक्षणिक उपलब्धियों तथा सुधार योग्य क्षेत्रों पर सामूहिक चर्चा की गई। समूहवार विचार-विमर्श के माध्यम से आगामी शैक्षणिक कार्ययोजना का प्रारूप तैयार किया गया। कार्यशाला में जनपद के सभी शैक्षिक संसाधन व्यक्तियों तथा नामित शिक्षकों ने सक्रिय सहभागिता की और शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता सुधार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्रथम दिवस सहभागिता, चिंतन और योजना निर्माण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी एवं परिणामकारी रहा। द्वितीय दिवस में तैयार की गई कार्ययोजना को अंतिम रूप देकर उसके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति निर्धारित की जाएगी, जिससे जनपद की शैक्षणिक गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

मुकीद बने भाकियू के प्रदेश सचिव

बहराइच। भारतीय किसान यूनियन (भानू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा के द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए जिले के विकास खण्ड जरवल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हसनापुर धवरिया निवासी मोहम्मद मुकीद सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद सईद को संगठन का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है। मनोनयन पत्र जारी करते हुए उत्तर प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और किसानों की आवाज बुलंद करने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस नियुक्ति से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि मोहम्मद मुकीद सिद्दीकी अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए भारतीय किसान यूनियन (भानू) की नीतियों और सिद्धांतों पर निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे।

सांसद बहराइच की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई दिशा की बैठक

बहराइच।

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद बहराइच डॉ. आनन्द कुमार गोंड की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, नानपारा विधायक राम निवास वर्मा, सांसद कैसरगंज करण भूषण सिंह के प्रतिनिधि सुनील सिंह, विधायक पयागपुर के प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी, सदर विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल के प्रतिनिधि अशोक जायसवाल, विधायक बलहा श्रीमती सरोज सोनकर के प्रतिनिधि आलोक जिंदल, भाजपा उपाध्यक्ष रणविजय सिंह सहित निकायों के अध्यक्ष, प्रमुखगण, समिति के सदस्यगण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारण्टी की समीक्षा के दौरान सांसद द्वारा उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देश दिया गया कि जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनकी सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दे। इसी प्रकार उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देष दिया कि स्वयं सहायता समूहों की संख्यात्मक सूची एवं लखपति दीदियों की सूची भी उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देष दिये गये। ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार का अधिक से अधिक कृषक लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए मण्डी सचिव को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा बाहरी मण्डी में उपज की बिक्री हेतु किसानों को सहयोग प्रदान करने के निर्देष दिये गये। उप निदेषक कृषि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत भुगतान की गयी धनराषि व कृषको की सूची मा. जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करने के निर्देष दिये गये। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की समीक्षा के दौरान सांसद द्वारा निर्देष दिया गया कि समस्त चिन्हित स्थानों पर षीघ्र से षीघ्र जन औषधि केंद्रों को संचालित कर आमजन को सभी अनुमन्य औषधियां उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने जन औषधि केन्द्रों पर वेण्डर नामित किये जाने के निर्देष दिये गये। बैठक के दौरान जिला दिव्यांगजन सषक्तिकरण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 03 व 25 दिसम्बर 2025 को विकास भवन व महराज सिंह इण्टर कालेज में दिव्यांगजनों को जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में सहायक उपकरणों का वितरण कराया गया है। इस सम्बंध में सभी पात्र दिव्यांगजनों को विभागीय योजनाओं से आच्छादित किया जाय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान सांसद डॉ. गोंड द्वारा सुझाव दिया गया कि जो मार्ग अतिआवश्यक है उनके प्रस्ताव की प्रति जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दी जाय। सांसद ने निर्देश दिया कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को ऋण दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाय तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जाय। बैठक के दौरान अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, राष्ट्रीय पशु रोग नियमंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान, एकीकृत बाल विकास योजना, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 1.0, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, ई-श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना इत्यादि योजनाओं की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया गया कि सदन में प्राप्त हुए निर्देशों तथा सुझावों का आगामी बैठक से पूर्व अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इससे पूर्व डीएम व मुख्य विकास अधिकारी मुकेष चन्द्र द्वारा बैठक में आये हुए जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी ने किया। इस अवसर पर डीएफओ बहराइच सुंदरेषा व कतर्नियाघाट अपूर्व दीक्षित, सीएमओ डॉ संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी राज कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

चन्द्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश

मुरादाबाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, महानगर मुरादाबाद की एक महत्वपूर्ण बैठक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आयोजित की गई। ज्ञातव्य है कि आजाद जी परम देशभक्त, साहसी, निडर एवं वीर क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी तथा अंग्रेजी शासन का हर स्तर पर विरोध किया। वे प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका शारीरिक स्वास्थ्य अत्यंत सुदृढ़ था। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि विरोधी भी उनके सामने आने का साहस नहीं कर पाते थे। अंग्रेज उनके नाम मात्र से ही भयभीत हो जाते थे। उन्होंने मातृभूमि की सेवा को अपने जीवन का सर्वो'च लक्ष्य बनाया। वे सदैव हम सभी के हृदय में अमर रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ चंद्रशेखर आजाद जी के चित्र पर पुष्पमाला एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने हाथ जोड़कर उनके प्रति श्रद्धा, वंदन एवं नमन व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉ. प्रदीप शर्मा, विमलेंद्र शर्मा विमल, सत्येंद्र शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, हितेश मिश्रा, राकेश शर्मा अमित शर्मा, राजू शर्मा, रणवीर शर्मा, आशुतोष शर्मा, विशाल शर्मा, प्रदीप प्रभाकर, दीपक शर्मा, संजय स्वामी आदि उपस्थित रहे।

दिल्ली में लॉन्च होगा सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, अब महिलाओं को ही नहीं इन्हें भी मिलेगी फ्री बस सेवा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार 2 मार्च को सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड लॉन्च करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले एक समारोह में इसे लॉन्च करेंगी। ये पिंक कार्ड मिलने से महिलाओं को अब पिंक टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इन कार्ड से वे बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी। सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाएं ही इस फायदे के लिए एलिजिबल होंगी। यह कार्ड डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं/ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त सफर के लिए फेयर टिकट की जगह लेगा। इसमें 12 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त, सुरक्षित और आसान बस सफर मिलेगा। यह कार्ड एक NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) होगा, जो डीटीसी और क्लस्टर बसों में वैलिड होगा। कार्ड पाने के लिए एप्लिकेंट के पास दिल्ली का आधार कार्ड होना जरूरी होगा। स्मार्ट कार्ड स्कीम शुरू होने के बाद ... शुरू किया जाएगा। दिल्ली में रहने ...

डीटीसी के मुताबिक, पिंक सहेली ... ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस ... वाली महिलाएं ऑनलाइन अप्लाई कराके यह स्मार्ट कार्ड पा सकेंगी। जिन महिलाओं के पास पिंक कार्ड नहीं होगा, वे मुफ्त सफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक और मफिन पेमेंट्स बैंक को स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए ऑथराइज्ड किया है। तीन तरह के स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहला पिंक सहेली कार्ड होगा, जो दिल्ली में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए जरूरी होगा और इसमें पूरी तरह से फ्री यात्रा मिलेगी। दूसरा कार्ड खास कैटेगरी जैसे दिव्यांग, बुजुर्ग, खिलाड़ी, युद्ध विधवाओं और नेशनल अवॉर्ड विजेताओं के लिए होगा। तीसरा सभी यात्रियों के लिए एक जनरल स्मार्ट कार्ड होगा, जो मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड के लिए कम से कम ₹120 का पेमेंट करना होगा, और केवाईसी के हिस्से के तौर पर नाम और फोटो रजिस्टर किया जाएगा। दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर कार्ड जारी करने वाले बूथ बनाए जाएंगे। इनमें बड़े डिपो, पास सेंटर और ऑथराइज्ड बैंकों की चुनी हुई जगहें भी शामिल होंगी। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड स्कीम के लॉन्च पर दिल्ली सरकार ने कुछ और घोषणाएं भी की। इस मौके पर गरीब राशन कार्ड होल्डर्स के लिए हर साल दो मुफ्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर शुरू करने के प्लान की घोषणा की है।

अरविंद केजरीवाल का चैलेंज, दिल्ली में चुनाव करा लें, बीजेपी को 10+ सीट आई तो छोड़ दूंगा राजनीति

कोर्ट बोला- सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ी, आखिर में सच की जीत होती है- केजरीवाल

केजरीवाल-सिसोदिया बरी
Delhi E&cise Policy केस के CBI अफसर पर होगी जांच

नई दिल्ली। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा, आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है। इसके बाद से केजरीवाल और सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। आप दफ्तर पहुंचने के बाद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज बहुत ऐतिहासिक जीत हुई। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन आज जज साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई। साबित हो गया कि केजरीवाल बहुत कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल ने आगे कहा, मैं कोई नेता नहीं, मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई। बीजेपी वालों ने मेरे पीछे ईडी-सीबीआई और पुलिस को लगा दिया गया था। मैं जब जेल में था तो मेरी माँ बीमार थी। मेरे परिवार ने बहुत कुछ भुगता है। उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो दोबारा चुनाव करवाओ। आज कोर्ट को यह तय करना था कि मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत और गवाह है या नहीं।

कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया

केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने 600 पेज की चार्जशीट देखी और पाया कि मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत या गवाह काफी नहीं है। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि केस इतना कमजोर है कि मुकदमा चलाने के लिए एक भी सबूत नहीं है। उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी, 2026 आम आदमी पार्टी के लिए एक अहम दिन है, जो भ्रष्टाचार से लड़कर सत्ता में आई और फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सत्ता से बाहर हो गई। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया।

देश से माफी मांगें पीएम नरेंद्र मोदी- संजय

केजरीवाल और सिसोदिया के आरोप मुक्त करार दिए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अदालत ने अपने फैसले में कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने देश के सबसे ईमानदार दल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा और आज यह षड्यंत्र नाकाम हो गया। अब अगर प्रधानमंत्री में जरा भी शर्म बची है तो वह पूरे देश से माफी मांगें और कहें कि उन्होंने आप को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी, भाजपा की तानाशाही के सामने चट्टान की तरह डटकर लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से सुधारों पर अपना एजेंडा पेश करने को कहा

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुधारों को लेकर महत्वाकांक्षी एजेंडा सामने रखते हुए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से कहा है कि वे अपने-अपने मंत्रालयों में आने वाले वर्षों में किए जाने वाले सुधारात्मक कदमों पर विस्तृत नोट तैयार करें। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह कवायद सरकार के सुधारों पर केंद्रित रिफॉर्म एक्सप्रेस एजेंडा का हिस्सा है जिसके तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कारोबारी सुगमता में सुधार करना और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन का दायरा बढ़ाना लक्ष्य है। मंत्रियों से कहा गया है कि वे यह नोट स्वयं तैयार करें और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उसे पेश कर अपने मंत्रालय की गतिविधियों और सुधार दृष्टिकोण की जानकारी दें। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने एक निर्धारित प्रारूप प्रसारित किया है, जिसमें हरेक मंत्रालय को पिछले कुछ वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों के साथ भविष्य की सुधार पहलों का विवरण देना होगा। इस प्रारूप में यह स्पष्ट करना होगा कि सुधार कब लागू किए गए या कब प्रस्तावित हैं और उन सुधारों से क्या परिणाम अपेक्षित हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हरेक मंत्रालय अपने सुधार एजेंडे को प्राथमिकता दे ताकि उसके परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई दें। यह समूची प्रक्रिया वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की व्यापक रूपरेखा का हिस्सा मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि उनकी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस से आम नागरिकों को व्यापक लाभ मिल रहा है। अगले दशक की शीर्ष प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारी दिशा स्पष्ट है, इसे किसी निश्चित संख्या तक सीमित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त विषय पर आयोजित एक बजट-पश्चात वेबिनार में सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्थानों और अकादमिक जगत के बीच सहयोग के लिए सुधार साझेदारी चार्टर विकसित करने का सुझाव भी दिया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग का किया दौरा, नई परियोजनाओं का किया शुभारंभ

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीतमपुरा के पीयू ब्लॉक में नई सीवर लाइन बिछाने की परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना लंबे समय से चली आ रही सीवर संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके पूरा होने पर क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था अधिक सुचारु और स्वच्छ होगी। मुख्यमंत्री ने क्यूयू ब्लॉक में सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। अधिकारियों के अनुसार, इन कार्यों के पूरा होने से जलभराव की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी और स्थानीय निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त, पीतमपुरा स्थित आउटर रिंग रोड पर एसयू-टीयू-एमयू, टीयू-एसयू-यूयू और एलयू-क्यूयू ब्लॉकों की सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा तथा लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजधानी में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष में शालीमार बाग क्षेत्र की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीयू ब्लॉक में जर्जर सीवर लाइनों को बदलने का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि क्यूयू ब्लॉक में नई लेन और नालियों के निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। आउटर रिंग रोड से जुड़े विभिन्न ब्लॉकों में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों को भी जनता को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं, ताकि नागरिकों को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सीवर, सड़क, ड्रेनेज और अन्य शहरी सुविधाओं के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे राजधानी के हर क्षेत्र में स्वच्छता, सुगमता और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

- **फैसला सुरक्षित; सरकारी वकील ने कहा- वो बहुत पावरफुल, केस प्रभावित करेंगे**
- **नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में दर्ज पाक्सो केस में नामजद हैं**
- **शुक्रवार शाम करीब एक घंटे से भी अधिक समय तक चली सुनवाई**

प्रयागराज।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में दर्ज पाक्सो केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार शाम करीब एक घंटे से भी अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद खचाखच भरी कोर्ट में न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाया। यह फैसला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के आदेश के क्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व अन्य के खिलाफ बीते रविवार को झूंसी थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। झूंसी पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ कर चुकी है। पीड़ितों का बयान और मेडिकल भी हो चुका है। माघ मेला तथा महाकुंभ में नाबालिगों के साथ कुकर्म का आरोप स्वामी और उनके सहयोगी स्वामी मुकुंदानंद के खिलाफ है। सुनवाई से पहले ही कोर्ट नंबर 72 खचाखच भर गई थी। बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को नाबालिग बताया। पीड़ितों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया।

यौन शोषण मामले में सच सामने लाने को नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं - अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में यदि सच्चाई का पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट जरूरी हो तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, «यदि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ सकती है तो यह अवश्य किया जाना चाहिए। सच उजागर करने के लिए जो भी तरीके उपलब्ध हैं, उन्हें अपनाया जाना चाहिए। नार्को टेस्ट एक वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया है, जिसमें किसी संदिग्ध को सोडियम पेंटोथल जैसी दवा दी जाती है। इसके असर से वह पूरी तरह होश में नहीं रहता, लेकिन सवालों के जवाब दे सकता है जिससे उसके सच बोलने की संभावना बढ़ जाती है। यह टेस्ट अदालत की अनुमति और व्यक्ति की सहमति के बाद विशेषज्ञों की निगरानी में ही होता है। संत की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपराह्न करीब पौने चार बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। उनके शिष्य संजय पांडे ने बताया कि स्वामी अपनी नियमित धार्मिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और उन्होंने प्रतिदिन की तरह पूजा-अर्चना की। मठ में बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे।

झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता- अविमुक्तेश्वरानंद

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके वकील अदालत में उपस्थित हैं और सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा, झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। जिन्होंने झूठी कहानी गढ़ी है, वे बेनकाब हो रहे हैं। जैसे-जैसे लोगों को इस मनगढ़ंत मामले की जानकारी होगी, सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। मेडिकल जांच रिपोर्ट से जुड़े दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, एक मेडिकल रिपोर्ट हमारी संलिप्तता कैसे साबित कर सकती है? कहा जा रहा है कि रिपोर्ट से दुराचार सिद्ध हुआ है। यह किसी का कथन हो सकता है, लेकिन इतने दिनों बाद की गई मेडिकल जांच का क्या महत्व है? उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत घटना हुई भी हो, तो इससे स्वतः यह सिद्ध नहीं होता कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, जो बच्चा कभी हमारे पास आया ही नहीं, उसे हमारे नाम से जोड़ना आसान नहीं है।

अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाए कई गंभीर आरोप

अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि बच्चे शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ पांडे के साथ रह रहे थे और सवाल उठाया कि उन्हें किशोर गृह क्यों नहीं भेजा गया। उन्होंने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए दावा किया कि बच्चों को हरदोई के एक होटल में रखा गया था और उन्हें पत्रकारों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने पुलिस पर शिकायतकर्ता को संरक्षण देने और उनके खिलाफ बयान तैयार कराने का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कहानी कितनी भी मनगढ़ंत क्यों न हो, सच्चाई अंततः सामने आएगी। इससे पहले बृहस्पतिवार को स्वामी ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज मामले को «झूठा» बताते हुए आरोप लगाया था कि यह उन्हें बदनाम करने और दुनिया भर में चर्चित एप्स्टीन फाइल्स से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में जिस संस्था का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत हेतु उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने यह भी कहा कि न तो उनका और न ही उनके गुरुकुल का शिकायतकर्ताओं से कोई संबंध है।

फर्जी एजेंटों पर वार, डंकी रूट पर प्रहार, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी सरकार - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हो युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसकी मदद के लिए 'विदेश सहयोग विभाग' बनाया गया है। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार व शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्षियों द्वारा रखी गई बातों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 'विदेश सहयोग विभाग' की वेबसाइट पर विदेश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेश भेजने वाले अधिकृत एजेंटों की सूची भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के माध्यम से युवा विदेश जाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सरकारी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सदन में प्रदेश के युवाओं से भी अपील करते हुए कहा कि वे

विदेश जाने के इच्छुक युवाओं के सहयोग के लिए सरकार का 'विदेश सहयोग विभाग' सक्रिय

मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- 'विदेश सहयोग विभाग' की वेबसाइट पर विदेश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध

गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के झांसे में न आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए और ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून भी बनाया जा चुका है। सरकार एचकेआरएनएल के माध्यम से लीगल रूट से विदेशों में युवाओं को भेज रही है। उन्होंने कहा कि एचकेआरएनएल को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस की सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इस विषय में समय-समय पर एचकेआरएनएल द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने गत 3 जनवरी को पंचजन्य-2026 कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके तहत प्रदेश के 210 युवाओं को दुबई जाने के लिए ऑफर लेटर दिए गए हैं। अब तक 2 चरणों में 390 युवाओं को इजराइल भेजा जा चुका है।

कोलकाता में लगे भूकंप के झटके, लोग इमारतों से बाहर भागे

बंगाल। शुक्रवार को बांग्लादेश में आए 5.4 तीव्रता के भूकंप के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास के कई जिलों में तेज झटके महसूस किए गए। अचानक आए इन झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और एहतियातन कई लोग दफ्तरों और इमारतों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भूकंप का केंद्र ढाका के अगरगांव स्थित BMD सिस्मिक सेंटर के दक्षिण-पश्चिम में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। कई लोगों के मोबाइल फोन पर आए भूकंप अलर्ट में तीव्रता करीब 5 बताई गई और केंद्र शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दर्शाया गया। कोलकाता के विभिन्न हिस्सों, खासकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक क्षेत्रों में मौजूद लोगों ने फर्नीचर के हिलने और इमारतों में कंपन महसूस होने की जानकारी दी। कई कमर्शियल हब में कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता को लेकर अनिश्चितता के बीच तुरंत इमारतें खाली कर दीं और खुले स्थानों पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

द केरल स्टोरी 2 पर बोली प्रियंका - बेहतर होगा शांति और प्रेम को बढ़ावा देने वाली फिल्में बनें

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने फिल्म द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड से जुड़े विवाद को लेकर शुक्रवार को कहा कि लोगों को खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि ऐसी चीजें बनाएं जो लोगों को खुशी दें और शांति, प्रेम और कल्याण को बढ़ावा दें। वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाद्रा ने फिल्म से जुड़े सवाल पर संवाददाताओं से कहा, «सबसे पहले, मुझे लगता है कि लोगों को खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही ऐसे माहौल में

जो एक-दूसरे के प्रति इस तरह की बयानबाजी, गुस्से और नफरत से भरा होता जा रहा है, रचनात्मक रूप से ऐसी चीजें बनाना बेहतर है जो खुशी दें और लोगों के बीच शांति, प्रेम और कल्याण को बढ़ावा दें। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वायनाड में भूस्खलन की घटना के बाद सभी ने एक-दूसरे की मदद की और अपने धर्म या जाति की परवाह किए बिना ऐसा करना जारी रखा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह वह भावना है जो वास्तव में भारत का सार और केरल की भावना है और यही इसके बारे में बहुत सुंदर है। केरल उच्च न्यायालय ने द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड के प्रदर्शन पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि फिल्म का प्रमाणन करते समय सेंसर बोर्ड ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। बाद में फिल्म के निर्माता ने इस फैसले को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी।

राजस्थान रोडवेज की चलती बस में लगी भीषण आग, 70 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

जयपुर। जयपुर में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब राजस्थान रोडवेज की एक चलती बस में अचानक आग लग गई। यह बस सिंधीकैंप बस स्टैंड से केकड़ी जा रही थी और इसमें करीब 70 यात्री सवार थे। घटना मानसरोवर रीको चौराहे के पास दोपहर करीब 2:40 बजे हुई। आग लगते ही बस में धुआं भर गया और कुछ ही पलों में लपटें उठने लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के अगले हिस्से से अचानक धुआं निकलता दिखा। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक लिया।

चालक और परिचालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी यात्रियों को जल्दबाजी में सुरक्षित नीचे उतारा गया। यात्री जैसे-तैसे बस से बाहर निकले और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। मानसरोवर फायर स्टेशन के फायरमैन के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बस के वायरिंग सिस्टम में लगी आग तेजी से फैलती हुई इंजन तक पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में बदल चुकी थी। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बस का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।